



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 68-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023 (CHAITRA 22, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 अप्रैल, 2023

नं० 605-कृषि.II (5)-2023/2649.— पंजाब गन्ना (खरीद एवं आपूर्ति के विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 के खण्ड (i) तथा इसके अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0148/पी0ए040/53/5.17/77 दिनांक 31 अक्टूबर, 1977 के माध्यम से किसी चीनी कारखाने द्वारा या उसकी ओर से गन्ने की खरीद पर एक रुपया पचास पैसे प्रति क्विंटल की दर से कर लगाया गया था। राज्य सरकार ने पाया कि सहकारी और निजी चीनी मिलों सहित हरियाणा की कुछ चीनी मिलों ने पिछले कई पेरार्ई सत्रों से बकाया खरीद कर और उस पर ब्याज जमा नहीं किया है और परिणामस्वरूप एक बड़ी राशि जमा हो गई है।

जीएसटी के 01.07.2017 से लागू होने को ध्यान में रखते हुए तथा बकाया गन्ना खरीद कर एवं उस पर ब्याज की वसूली के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम” अधिसूचित की जाती है।

1. बकाया ब्याज 30.06.2017 को, क्रय कर की बकाया राशि के बराबर राशि तक सीमित (Capped) है।
2. यदि अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर संबंधित चीनी मिल द्वारा पूरी राशि (बकाया मूलधन तथा कैप्ड ब्याज) का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे बकाया ब्याज (जैसा कि सीमित है) का 35 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा।
3. यदि संबंधित चीनी मिलों द्वारा पूरी राशि (बकाया मूलधन तथा कैप्ड ब्याज) का भुगतान 3 महीने के बाद परन्तु 6 महीने के भीतर किया जाता है, तो बकाया ब्याज (जैसा कि सीमित है) का 20 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा।

डॉ० सुमिता मिश्रा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE DEPARTMENT****Notification**

The 12th April, 2023

No. 605-Agri.II (5)-2023/2649.— In exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 17 of the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Act, 1953, and all other powers enabling him in this behalf, The Governor of Haryana had imposed a tax at the rate of one rupee and fifty paise per quintal on the purchase of cane by or on behalf of a sugar factory *vide* Notification No.S.O.148/P.A.40/53/5.17/77 dated 31st October, 1977. The State Government observed that some of the sugar mills of Haryana, including Cooperative and Private Sugar Mills, have not deposited outstanding purchase tax and interest thereon from last many crushing seasons and a huge amount is accumulated resultantly.

Taking a view of inception of GST from 01.07.2017 and for the purpose to recover the outstanding cane purchase tax and interest thereon, the State Govt. hereby notify a “One Time Settlement Scheme” with following conditions:-

1. The outstanding interest is capped to an amount equal to the outstanding amount of purchase tax, as on 30.06.2017.
2. If the entire amount (outstanding principal and interest subject to the cap) is paid by the concerned sugar mills within 3 months from the date of notification, 35% of such outstanding interest (as capped) will be waived off.
3. If the entire amount (outstanding principal and interest subject to the cap) is paid by the concerned sugar mills, after 3 months but within 6 months then 20% of the outstanding interest (as capped) will be waived off.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture & Farmers' Welfare Department.